वर्ष 12 • अंक 267 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 27 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 2

उड़ान दुरुस्त कर रही गोएयर

सचिन बंसल पृष्ठ 3

सचिन की फर्म ने मावेनहाइव का किया अधिग्रहण

डॉलर रु. 71.30 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 79.10 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38636 ▲ 345 रुपये | सेंसेक्स 41163.80 ▼ 297.50 | निफ्टी 12126.50 ▼ 88.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12195.80 ▲ 69.20 | ब्रेंट क्रूड 67.00 डॉलर ▲ 0.10 डॉलर

एक नज़र

आरबीआई सोमवार को बॉन्ड की खरीद-फरोख्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि वह सोमवार को खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा और इतनी ही मूल्य की प्रतिभूतियां बेचेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नकदी की स्थिति की समीक्षा के बाद उसने यह निर्णय लिया है। इस सप्ताह के शुरू में केंद्रीय बैंक ने ओएमओ के तहत 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियां खरीदी थी और 6,825 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियां बेची थीं। पृष्ठ 3

नए 5जी स्पेक्ट्रम के लिए ट्राई से राय लेगा डीओटी

दूरसंचार विभाग (डीओटी) 5जी बैंड में 24.75 से 27.25 गीगाहर्ट्ज के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के मूल्य और अन्य तौर तरीकों पर जल्द भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की राय लेगा। दूरसंचार विभाग का इरादा इस नए स्पेक्ट्रम की बिक्री अगले साल किसी समय करने का है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। डिजिटल संचार आयोग द्वारा 20 दिसंबर को 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दी गई है। यह नया 5जी स्पेक्ट्रम इससे अलग है। पृष्ठ 4

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के लिए आधार जरूरी

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना 'प्रधानमंत्री वय वंदन योजना' के ग्राहकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सालाना आठ फीसदी का रिटर्न देती है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना का संचालन करता है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के आम बजट में इसकी घोषणा की गई थी। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार क्रमांक या फिर आधार सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी देना जरूरी होगा।

241 करोड़ रुपये की कर चोरी का भांडाफोड़

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधिकारियों ने 1,600 करोड़ रुपये के फर्जी रसीदों के जरिये 241 करोड़ रुपये की कर चोरी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को इसकी जानकारी दी गयी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे एक स्थानीय अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में संलिप्त 120 से अधिक निकायों का पता चला है जिन्होंने 1,600 करोड़ रुपये के फर्जी रसीदों के जरिये 241 करोड़ रुपये की कर चोरी की है।

यात्री किराया व मालभाड़े की दर होगी अधिक तर्कसंगत

रेलवे यात्री किराया एवं माल भाड़े की दर अधिक तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया में है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि यादव ने यह बताने से इनकार कर दिया कि किराए में बढ़ोतरी होगी या नहीं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रेलवे ने राजस्व में कमी दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन किराया बढ़ाना एक संवेदनशील विषय हैं और इस पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले चर्चा करने की जरूरत है। पृष्ठ 4

व्यापार गोष्ठी

कारोबार के लिहाज से कैसा रहा साल 2019?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या एलआईसी को रिटर्न बढ़ाने के लिए इक्विटी पर लगाना चाहिए दांव

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या जीएसटी शिकायत के लिए अलग व्यवस्था से दूर होगी दिक्कत? हां **81.82%** नहीं **18.18%**

आईटी पर बोइंग 737 का ब्रेक

बोइंग 737 मैक्स संकट से आईटी कंपनियों को 1 अरब डॉलर की चपत की आशंका

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 26 दिसंबर

- जनवरी से रुकेगा बोइंग 737 मैक्स का उत्पादन
- बोइंग और उसके आपूर्तिकर्ताओं को सेवाएं देती हैं भारतीय कंपनियां
- टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजिज, इन्फोसिस, सायंट और एलऐंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का है अनुबंध
- बोइंग संकट से विमानन क्षेत्र का खर्च भी हो सकता है प्रभावित

विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा जनवरी से 737 मैक्स विमानों का उत्पादन रोके जाने से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को एक अरब डॉलर से अधिक की चपत लग सकती है।

सूत्रों के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचसीएल टेक्नोलॉजिज, इन्फोसिस, सायंट और लार्सन ऐंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसी देश की दिग्गज आईटी कंपनियों का बोइंग या उसे साजोसामान आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ अनुबंध है। इनमें इंजन और विमान का ढांचा बनाने वाली कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक साजोसामान मुहैया कराने वाली कंपनियां शामिल हैं। 737 मैक्स विमानों का उत्पादन बंद होने से भारतीय आईटी कंपनियों का बोइंग और उससे जुड़ी कंपनियों के साथ एक अरब डॉलर का अनुबंध खतरे में पड़ जाएगा।

आईटी आउटसोर्सिंग सलाहकार और पारीख कंसल्टिंग के संस्थापक पारीख जैन ने कहा, 'बोइंग कई भारतीय सेवा प्रदाताओं की शीर्ष दस ग्राहकों में शामिल है। जाहिर है कि इन कंपनियों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बड़ी चिंता यह है कि अगर बोइंग प्रभावित होती है तो इसका विमानन क्षेत्र में कुल खर्च में भी कमी आएगी।'

बोइंग ने इस महीने चौड़े आकार वाले 737 मैक्स विमानों का उत्पादन अस्थायी तौर पर रोका था और अब उसने अपने आपूर्तिकर्ताओं को जनवरी से आपूर्ति रोकने को कहा है। इंडोनेशिया और इथियोपिया में मैक्स 737 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कंपनी नियामकों का भरोसा जीतने के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले सप्ताह यह संकट उस समय और गहरा गया जब कंपनी ने अपनी मुख्य कार्याधिकारी डेनिस मूलनबर्ग को बाहर कर दिया।

अनुमानों के मुताबिक दुनिया में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग का सालाना बाजार 4 अरब डॉलर का है जिसमें बोइंग और एयरबस की बराबर हिस्सेदारी है। बोइंग हर साल 2 अरब डॉलर का आईटी का काम आउटसोर्स करती है जिसमें से आधे सौदे भारतीय सेवा प्रदाता कंपनियों की झोली में आते हैं। अभी बोइंग को आपूर्ति करने वाली कंपनियों में प्रेट ऐंड व्हिटनी, रॉल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरैन जैसी इंजन बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। साथ ही स्पिरिट एयरोसिस्टम्स और सैफरैन उसे विमान का ढांचा और कलपुर्जे मुहैया करती हैं। इसी तरह रॉकवेल और हनीवेल बोइंग की विभिन्न प्रणालियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति करती हैं।

आउटसोर्सिंग बाजार की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, 'अधिकांश भारतीय कंपनियां का बोइंग या उसे आपूर्ति करने वाली कंपनियों को सेवा प्रदान करती हैं। टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजिज और सायंट बोइंग को सेवा देती हैं जबकि स्पिरिट एयरोसिस्टम इन्फोसिस की ग्राहक है।' इस बारे में टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजिज, इन्फोसिस, सायंट और लार्सन ऐंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने ईमेल का जवाब नहीं दिया जबकि इन्फोसिस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ग्रेहाउंड रिसर्च के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी संचित वीर गोगिया ने कहा, 'अमूमन आउटसोर्सिंग अनुबंधों में आईटी कंपनियों को नुकसान से बचाने के उपाय होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से निकट भविष्य में इससे उनके मुनाफे पर चोट होगी।' (शेष पृष्ठ 2 पर)

एलआईसी का रिटर्न 8 साल में सबसे कम

कृष्ण कांत और सचिन मामबटा
मुंबई, 26 दिसंबर

औद्योगिक वृद्धि कम रहने और बॉन्ड प्रतिफल तथा ब्याज दरों पर दबाव के कारण नियत आय वाली प्रतिभूतियों और शेयर बाजार के देश में सबसे बड़े एकल निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के निवेश पोर्टफोलियो पर असर पड़ रहा है। 2018-19 में एलआईसी के निवेश पोर्टफोलियो का रिटर्न आठ साल के निचले स्तर 7.59 फीसदी रहा, जो पिछले साल की तुलना में 12 आधार अंक कम है। यह जानकारी एलआईसी ने वित्त वर्ष 2019 की अपनी सालाना रिपोर्ट में दी है।

एलआईसी के निवेश पर मार

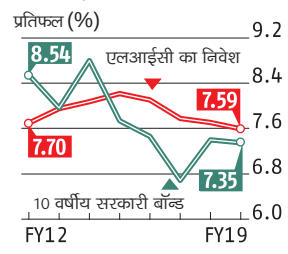

नोटः जी-सेक पर प्राप्ति संबंधित वित्त वर्ष का औसत है।
स्रोतः एलआईसी की सालाना रिपोर्ट
बीएस रिसर्च ब्योरो

इसके परिणामस्वरूप एलआईसी और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल का स्प्रेड पिछले वित्त वर्ष में पांच साल में सबसे कम 23 आधार अंक रह गया, जो इससे पिछले साल 31 आधार अंक था। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रतिफल में कमी मुख्य रूप से बीमा कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो की वृद्धि की तुलना में शुद्ध आय की वृद्धि कम रहने की वजह से आई है। वित्त वर्ष 2019 में एलआईसी के कुल निवेश पोर्टफोलियो 29.3 लाख करोड़ रुपये पर शुद्ध निवेश आय 2.2 लाख करोड़ रुपये रही। पिछले पांच वर्षों में निवेश पोर्टफोलियो सालाना 12.8 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर वित्त वर्ष 2014 के 16 लाख करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष में 29.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में एलआईसी के निवेश पर आय 9.3 फीसदी सीएजीआर से बढ़ी और वित्त वर्ष 2014 के 1.43 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में यह 2.22 लाख करोड़ रुपये हो गई।

एलआईसी मुख्य रूप से नियत आय वाले निवेश साधनों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी दीर्घावधि की डेट प्रतिभूतियां शामिल हैं। विश्लेषकों का कहना है कि नियम आय पोर्टफोलियो पर प्रतिफल 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। एलआईसी की सालाना रिपोर्ट के अनुसार उसके पोर्टफोलियो में शेयरों की हिस्सेदारी काफी कम है।

केआर चोकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रबंध निदेशक देवेन चोकसी ने कहा कि इक्विटी में निवेश बढ़ाने से उसे बेहतर रिटर्न हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि एलआईसी जैसे बड़े संस्थागत निवेशकों को इसमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जबकि छोटे निवेशकों के साथ ऐसा नहीं है। कई सूचीबद्ध कंपनियों के पास पूंजी आधार उतना नहीं होता है जो एलआईसी के बड़े निवेश को आकर्षित कर सकें।

उन्होंने कहा, 'एलआईसी जैसे बड़े निवेशकों के लिए शेयरों में बड़े निवेश के लिए लिक्विड शेयरों को तलाशना चुनौतीपूर्ण होता है। अगर शीर्ष 100 कंपनियों को छोड़ दें तो बाजार में उतनी गहराई नहीं है।'

इन्हीं बंदिशों की वजह से एलआईसी ज्यादा पूंजी वाले लिक्विड शेयरों वाले क्षेत्रों जैसे कि बैंकिंग, कंज्यूमर गुड्स, जिंस एवं ऊर्जा कंपनियां, बिजली, दूरसंचार, वाहन और पूंजीगत वस्तुओं से जुड़ी कंपनियों में निवेश करती है। इस क्षेत्र की कई कंपनियां पिछले पांच साल से औद्योगिक नरमी से जूझ रही हैं। इसकी वजह से भी एलआईसी के निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इस बारे में जानकारी के लिए एलआईसी को ईमेल भेजा गया लेकिन जवाब नहीं आया। ब्ल्यूओसन कैपिटल एडवाइजर्स के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी निपुन मेहता ने कहा कि एलआईसी को अपने पोर्टफोलियो को पारंपरिक निवेश से इतर से विस्तार करना चाहिए ताकि उसे ज्यादा प्रतिफल मिल सके। ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'पहले, इक्विटी में ज्यादा निवेश किया जा सकता है जिससे प्रतिफल में इजाफा होगा। दूसरा तरीका ज्यादा जोखिम वाला निवेश जैसे रीट या इनविट हो सकता है।'

बैंक की उधारी वृद्धि औंधे मुंह गिरी

सुब्रत पांडा और अभिजित लेले
मुंबई, 26 दिसंबर

- वित्त वर्ष 2020 में 6.5 से 7 फीसदी रही बैंक की उधारी वृद्धि
- निजी निवेश में कमी से उधारी की मांग में आई कमी
- अर्थव्यवस्था में नरमी की वजह से बैंकों की उधारी वृद्धि हुई प्रभावित

अर्थव्यवस्था में नरमी आने से बैंक द्वारा दी जाने वाली उधारी वृद्धि की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपने आकलन में कहा है कि कंपनियों द्वारा कार्यशील पूंजी की जरूरत कम होने और ऋणदाताओं द्वारा जोखिम से बचने की वजह से वित्त वर्ष 2020 में बैंकों की उधारी वृद्धि 6.5 से 7 फीसदी रही।

6 दिसंबर, 2019 तक बैंक उधारी महज 80,000 करोड़ रुपये बढ़ी जबकि वित्त वर्ष 2019 में इसी अवधि में 5.4 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018 (दिसंबर 2017 तक) में 1.7 लाख करोड़ रुपये का कर्ज आवंटित किया गया था। बैंकरों का कहना है कि निजी निवेश एक तरह से थम जाने से कंपनियों की ओर से उधारी मांग सीमित हो गई। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में गतिविधियां थोड़ी तेजी जरूरत हुई हैं लेकिन पूरे साल की नरमी की भरपाई करने में वह सक्षम नहीं है। कंपनियां दबाव में हैं और खुदरा क्षेत्र में भी उतनी तेजी नहीं है कि इस कमी की भरपाई कर सके।

इक्रा के आकलन के अनुसार 37 अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधारी वृद्धि सितंबर 2019 तक सालाना आधार पर 7.9 फीसदी बढ़ी। इनमें भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उधारी में 4.4 फीसदी का इजाफा हुआ जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस दौरान उधारी देने में 15 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक दिनेश खारा ने कहा, 'आर्थिक वृद्धि में नरमी से निजी क्षेत्र के निवेश और खपत पर असर पड़ा है। इससे चालू वित्त वर्ष में उधारी वृद्धि में भी कमी आई है। हालांकि अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।'

वित्त वर्ष 2019 में बैंक उधारी वृद्धि 12 लाख करोड़ रुपये रही जबकि वित्त वर्ष 2018 में यह 6.5 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2019 में काफी वृद्धि देखी गई जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की वजह से हो सकती है। आईएलऐंडएफएस संकट के बाद एनबीएफसी अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए बैंकों से संपर्क साधा था।

इक्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में बैंक की उधारी 6.5 से 7 लाख करोड़ रुपये बढ़ सकता है जो सालाना आधार पर 40 से 45 फीसदी कम रहेगा। (शेष पृष्ठ 4 पर)

गिग वर्कर्स को मिलेगी सस्ती स्वास्थ्य सेवा

गिग इकॉनमी से जुड़ी कंपनियों को अपने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवर में अंशदान की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है। इसकी जगह सरकार इन कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अस्पतालों और दवाखानों में सब्सिडी वाली दरों पर सस्ती चिकित्सा सेवा मुहैया कराने पर विचार कर रही है। पिछले महीने सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया था। इसमें गिग इकॉनमी में काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा कवर देने का प्रस्ताव है। उबर, ओला के चालकों, जोमैटो और स्विगी के डिलिवरी पहुंचाने वालों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। विधेयक में कहा गया है कि सरकार ईएसआईसी के तहत गिग कर्मचारियों को लाने के लिए एक योजना पेश करेगी। पृष्ठ 4

ऊंची उड़ान के बाद अर्थव्यवस्था अब ढलान पर

मिहिर शर्मा
नई दिल्ली, 26 दिसंबर

एक दशक में बदला परिदृश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2010 का दशक बेहद उतारचढ़ाव वाला रहा। वर्ष 2010 में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश की शुरुआत बहुत अच्छी रही। लग रहा था कि भारत ने कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर ढंग से वैश्विक वित्तीय संकट का सामना किया है और वह सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के मामले में रिकॉर्ड स्तर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी कारकों की कमजोरी और नोटबंदी तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दोहरे झटके के कारण सुस्ती से जूझ रही है। इस बीच यह एक बार पटरी पर लौटी थी और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद इसने गति पकड़ी थी। अब यह कई अनसुलझी समस्याओं के साथ इस दशक को अलविदा कहने जा रही है। इनमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या भी शामिल है जिसकी शुरुआत 10 साल पहले हुई थी। साथ ही अब जीडीपी और निवेश की रफ्तार रसातल में है जबकि बेरोजगारी चरम पर है। यहां हम पांच ऐसी हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं जो 2010 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की दास्तां का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं।

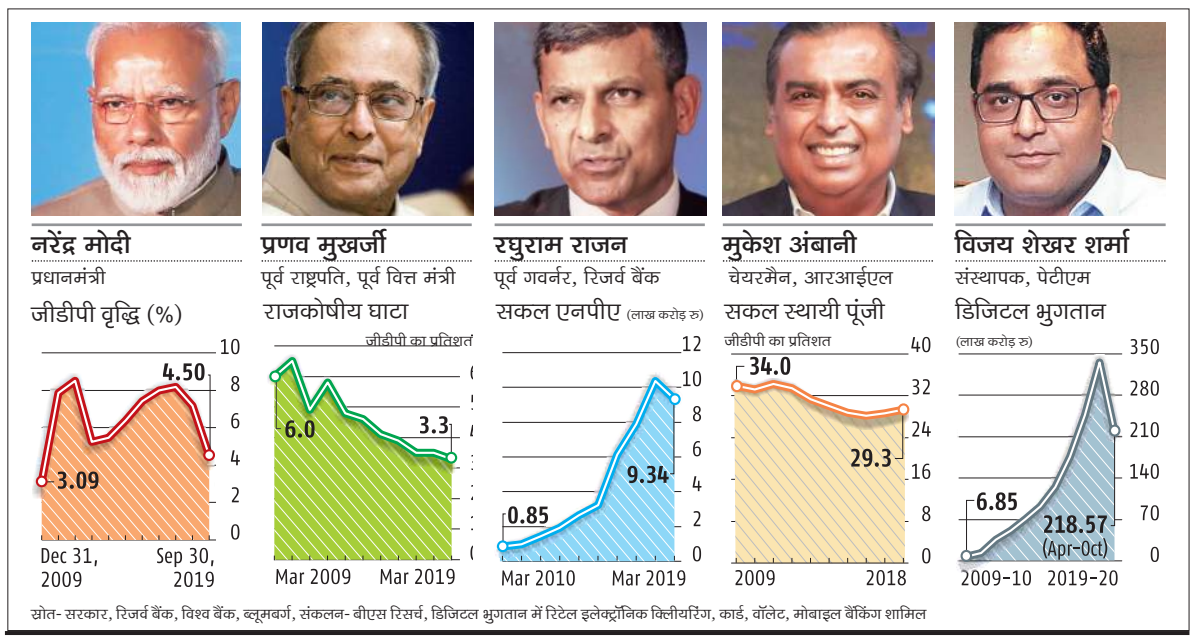

स्रोत- सरकार, रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, ब्लूमबर्ग, संकलन- बीएस रिसर्च, डिजिटल भुगतान में रिटेल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग, कार्ड, वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग शामिल

नरेंद्र मोदी : इसमें कोई दोराय नहीं है कि इस दशक में देश में जिस एक शख्स का दबदबा रहा, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति पर बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी अपनी छाप छोड़ी। हालांकि 2013-14 में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की बात कही थी। लेकिन अपने पहले कार्यकाल में मोदी कई मायनों में बाजार में सुधार की मुहिम से पीछे हट गए। राहुल गाधी ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि वह सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। निजीकरण के प्रयास सही मायने में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए और व्यापार उदारीकरण की मुहिम भी आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली गई क्योंकि भारत ने टैरिफ की दीवारें खड़ी कर दीं। मोदी की राजनीतिक पूंजी, उनका निर्विवाद नेतृत्व और बड़े फैसले लेने की उनकी मंशा के कारण पहले कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए। इनमें दिवालिया कानून और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल हैं। उन्होंने नोटबंदी जैसे कुछ नुकसानदायक फैसले भी लिए। मोदी सरकार के शुरुआती वर्षों में अर्थव्यवस्था को लेकर जो उम्मीद जगी थी, अब वह क्षीण होने लगी है और भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के साथ 2020 के दशक में प्रवेश कर रही है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

एनटीपीसी

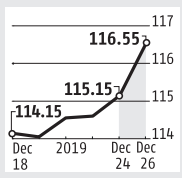

2022 तक 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना

₹ 115.15 पिछला बंद भाव
₹ 116.55 आज का बंद भाव
▲ 1.22 %

ओएनजीसी

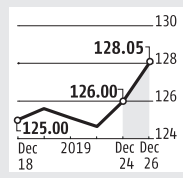

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 126.00 पिछला बंद भाव
₹ 128.05 आज का बंद भाव
▲ 1.63 %

द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज

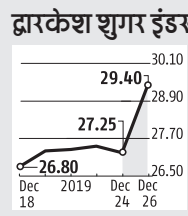

चीनी उत्पादक कंपनियों के शेयर अनुकूल चक्र में

₹ 27.25 पिछला बंद भाव
₹ 29.40 आज का बंद भाव
▲ 7.89 %

एसएमएल इसुजू

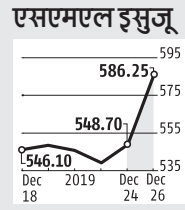

इक्रा ने दीर्घावधि रेटिंग घटाई

₹ 548.70 पिछला बंद भाव
₹ 586.25 आज का बंद भाव
▲ 6.84 %

इगारसी मोटर्स इंडिया

तीन सत्रों में 63 फीसदी चढ़े वाहन कलपुर्जा बनाने वाली कंपनियों के शेयर

₹ 334.35 पिछला बंद भाव
₹ 398.65 आज का बंद भाव
▲ 19.23 %

संक्षेप में

डिशमैन कार्बोजेन के दफ्तर में आयकर विभाग का छापा

डिशमैन कार्बोजेन एमिक्स लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि आयकर विभाग ने उसके दफ्तर और विनिर्माण इकाइयों में तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान 25 दिसंबर को समाप्त हो गया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, आयकर विभाग के अधिकारियों ने कंपनी के कार्यालयों और विनिर्माण इकाइयों में तलाशी की कार्रवाई की। तलाशी के दौरान कंपनी ने अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। अधिकारियों की ओर से मांगी गई सभी जानकारियां मुहैया कराई गई। *भाषा*

मणप्पुरम फाइनैंस एनसीडी से जुटाएगी रकम

मणप्पुरम फाइनैंस लिमिटेड ने निजी नियोजन के आधार पर गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 350 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल की वित्तीय संसाधन एवं प्रबंधन समिति ने गुरुवार को 10 लाख अंकित मूल्य के गारंटी और रेटिंग वाले विमोच्य गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 350 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है। सूचना में कहा गया है कि वित्तीय संसाधन एवं प्रबंधन समिति की 31 दिसंबर को भी बैठक होगी। *भाषा*

उड़ान सेवा दुरुस्त कर रही गोएयर

विमानन कंपनी ने कहा, इस सप्ताहांत तक सामान्य हो जाएंगी सेवाएं

अनीश फडणीस
मुंबई, 26 दिसंबर

प्रमुख विमानन कंपनी गोयर ने इस सप्ताह के आरंभ में अपनी दर्जनों उड़ानें रद्द करने के बाद आज कहा कि इस सप्ताहांत तक उसी सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। इसके लिए विमानन कंपनी अपने उड़ान परिचालन विभाग को सुदृढ़ कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि विमानन कंपनी रोस्टरिंग इकाई में नियुक्तियां कर रही है। यही इकाई पायलटों को उनकी छुट्टियों, बीमारी, प्रशिक्षण जरूरतों आदि को ध्यान में रखते हुए उड़ानों का आवंटन और क्रू ड्यूटी का प्रबंधन करती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान इस इकाई से कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। देरी और डायवर्जन की स्थिति में टीमवर्क काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि उथल-पुथल के दिन अथवा अगले कुछ दिनों तक नए सिरे से ड्यूटी का आवंटन करना होगा।

गोएयर ने नियुक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन आज एक बयान जारी कर कहा, 'गोयर के पास 325 रोजाना उड़ानों के लिए पर्याप्त कॉकपिट क्रू संसाधन उपलब्ध है। हालांकि बाहरी कारणों से उसकी समय-सारणी में तात्कालिक बदलाव दिख रहा है। विमानन कंपनी अपने पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों की मदद से परिचालन सामान्य करने के लिए काम कर रही है और उसे उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक सेवाएं सामान्य हो जाएंगी।'

हालांकि गोयर के पायलट रैंक में कमी की शिकायत कर रहे हैं और उनका दावा है कि छुट्टियों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। पिछले महीने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के एक ऑडिट में पाया गया कि इस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को नियमों के अनुसार आराम नहीं करने दिया। कुछ मामलों में पायलटों ने लगातार चार रातों की ड्यूटी की। जबकि नियमों के अनुसार इस प्रकार की केवल दो ड्यूटी करने की अनुमति है। गोएयर ने कहा कि उसने हमेशा से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के दिशानिर्देशों का पालन किया है जिसमें पायलटों की ड्यूटी से संबंधित नियम भी शामिल हैं।

गोएयर ने 23 और 24 दिसंबर को करीब 40 उड़ानें रद्द दी थी और उस दौरान कुहासे के कारण उसके दो विमानों के लौटने की भी चर्चा थी। विमानन कंपनी ने कहा था कि पिछली समय-सारणी में बदलाव और नए पायलटों के ड्यूटी समय संबंधी नियमों को लागू करने के कारण ऐसा हुआ। विमानन कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि एयरबस ए320 नियो विमानों की आपूर्ति में देरी और पुराने विमानों में इंजन बदलने के लिए उसकी उपलब्धता न होने से भी सेवाओं पर असर पड़ा। गोएयर ने कहा कि नवंबर और दिसंबर में एयरबस की डिलिवरी में देरी हुई और उससे चुनियां बढ़ गईं।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 3,000 से अधिक घंटे उड़ान भर चुके सभी विमानों में प्रैट ऐंड व्हिटनी इंजन लगाने का आदेश दिया था। विमानन कंपनी ने कहा कि वह नियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी और अगले महीने के अंत तक इंजन में सुधार की प्रक्रिया पूरी कर लेगी।

उड़ान सेवा

■ गोएयर ने 23 और 24 नवंबर को करीब 40 उड़ानें रद्द दी थी

■ विमानन कंपनी अपने उड़ान परिचालन विभाग को सुदृढ़ कर रही

बोइंग 737 मैक्स संकट से आईटी फर्मों को चपत

पृष्ठ 1 का शेष...

हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि सभी आपूर्तिकर्ता बोइंग के साथ लंबे समय तक काम करने को लेकर आश्वस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि कंपनी जल्दी ही इस स्थिति से उबर जाएगी।

बोइंग में जारी संकट के कारण उत्पादन के साथ कारोबार और बिक्री भी प्रभावित हुई है। लेकिन इसके बावजूद बोइंग की इंजीनियरिंग सेवा कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एक अन्य आउटसोर्सिंग सलाहकार ने कहा कि अगर 737 मैक्स का उत्पादन बंद होता है तो बोइंग 797 जैसे दूसरे विमानों पर निवेश बढ़ा सकती है। इससे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा कंपनियों को मदद मिलेगी।

बोइंग 797 कंपनी का दूसरा नया विमान कार्यक्रम है जिसमें 225 और 275 सीटों के विमान बनाए जा सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए भारतीय कंपनियों को ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एवियोनिक्स, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आदि सेवाएं मुहैया कराने का मौका मिल सकता है।

दीपक जैन बने एथर एनर्जी के मुख्य वित्त अधिकारी

हीरो मोटोकॉर्प समर्थित इलेक्ट्रिक दोपहिया स्टार्टअप एथर एनर्जी ने गुरुवार को दीपक जैन को मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया। कंपनी ने एक बयान में बताया कि जैन इससे पहले ऐपल इंडिया, पीऐंडजी और जिलेट जैसी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। उनके पास 20 साल से अधिक का अनुभव है। एथर एनर्जी के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण मेहता ने कहा कि जैन प्रौद्योगिकी व उत्पाद केंद्रित कंपनियों में काम कर चुके हैं। *भाषा*

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण को झटका

अदिति दिवेकर
मुंबई, 26 दिसंबर

केंद्र सरकार कई साल की अनिश्चितता के बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण की योजना बना रही है। लेकिन इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि यदि जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई अथवा उसमें देरी हुई तो दीर्घावधि में कारोबार प्रभावित हो सकता है।

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक पूर्व चेयरमैन ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'विनिवेश की खबर आते ही कंपनी में लगभग सभी तरह के निर्णय थम से गए थे। लंबी अवधि के अनुबंध वाले ग्राहकों ने नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया है और कारोबारी स्थिति कहीं अधिक अस्तव्यत हो जाएगी।'

अप्रैल 2003 में विनिवेश पर कैबिनेट कमेटी ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में विनिवेश को टालने का निर्णय लिया था। लेकिन अब उस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया गया है। सरकार ने विदेशी कंपनियों को पूरी 51 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की अनुमति दे रही है।

शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में प्रवर्तक हिस्सेदारी 30 सितंबर के अनुसार 63.75 फीसदी थी। शेष 36.25 फीसदी हिस्सेदारी आम शेयरधारकों के पास है। पूर्व चेयरमैन ने कहा, 'यह कोई पहला अवसर नहीं है जब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विनिवेश योजना की घोषणा की है। इससे पहले 2003 में सभी निर्णय आभासी तौर पर रुक गए थे। इस प्रकार की देरी से लंबी अवधि में कंपनी को नुकसान होगा। सरकार को इस पर गौर करने की जरूरत है।'

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, फरवरी 2019 में उसके बेड़े में 60 जहाज शामिल थे। उसके पास टैंकर, बल्क कैरियर, लाइनर और ऑफशोर आपूर्ति उपलब्ध है। इंडियन नैशनल शिपओनर्स एसोसिएशन के मुख्य कार्याधिकारी अनिल देवली ने कहा, 'विनिवेश चर्चा के दौरान आमतौर पर जहाजों की खरीद एवं बिक्री प्रभावित होती है क्योंकि निवेश निर्णय काफी प्रभावित होता है।'

गेल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जहाजरानी सेवाओं के बंधन के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ उनकी कंपनी का अनुबंध अभी जारी है। उन्होंने कहा, 'इससे पहले हमने नामांकन आधार पर इस राष्ट्रीय जहाजरानी कंपनी के साथ अनुबंध किया था। लेकिन इसके निजीकरण होने पर कंपनी को किसी अन्य निजी जहाजरानी कंपनी के तौर पर देखा जाएगा।'

वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में कंपनी के पास महज 95 करोड़ रुपये की नकदी एवं नकदी समतुल्य परिसंपत्ति थी जबकि वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत से पहले 2006-07 में यह आंकड़ा 2,625 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2015 में सुदृढ़ीकरण के बाद उसके नकदी एवं नकदी समतुल्य परिसंपत्तियों में गिरावट आई है। विनिवेश योजना से कंपनी का कामकाज प्रभावित हुआ है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमारे लिए कारोबार सामान्य है। हमारा बेड़ा भी आईएमओ 2020 के लिए तैयार है।' कंपनी के प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी के लिए भेजे ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। सरकार ने इस रणनीतिक बिक्री के लिए आरबीएसए को लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया है। पिछले सप्ताह सरकार ने एचके जोशी को कंपनी का पूर्णकालिक चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की भी घोषणा की थी।

उद्योग के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी वीएलसीसी यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर और एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस श्रेणियों में मौजूद है जो कारोबार के लिहाज से अच्छा है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के साथ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दीर्घावधि अनुबंध है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को तोहफा

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने गुरुवार को कहा कि अब उसके ग्राहक रात-दिन किसी भी समय नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सुविधा का इस्तेमाल करके पैसे भेज सकते हैं। रिजर्व बैंक के जारी दिशा-निर्देशों के तहत यह सुविधा दी गई है।

कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह सुविधा ग्राहकों को सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। यहां तक कि ग्राहक छुट्टियों में भी इसका उपयोग कर सकेंगे। वह इस सुविधा के जरिये कभी भी किसी भी बैंक में धन भेज या प्राप्त कर सकेंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप या एयरटेल पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट पर जाकर एनईएफटी के माध्यम से पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ट्रांसफर मनी विकल्प का चुनना होगा, जिसके बाद ट्रांसफर टू बैंक का विकल्प आएगा। *भाषा*

पैनासोनिक लगाएगी श्रीसिटी में नई फैक्टरी

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 26 दिसंबर

पैनासोनिक कॉरपोरेशन ने आज एक योजना की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि वह भारत में विनिर्माण का विस्तार करेगी। पैनासोनिक लाइफ सॉल्युशंस कंपनी की इकाई पैनासोनिक लाइफ सॉल्युशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वायरिंग उपकरण, इलेक्ट्रिक वायर और स्विचगियर के उत्पादन के लिए नई फैक्टरी लगाएगी और इस पर 294.6 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

आंध्र प्रदेश में श्रीसिटी इंडस्ट्रियल पार्क में नई फैक्टरी पैनासोनिक की इस चौथा इलेक्ट्रिक उपकरण उत्पादन का देश में चौथा आधार होगा और यहां साल 2021 में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। साल 2030 तक जीडीपी की रफ्तार 6 फीसदी रहने के अनुमान से न सिर्फ बड़े शहर बल्कि छोटे शहर भी आगामी वर्षों में आगे बढ़ेंगे। कार्यालय व हाउसिंग के निर्माण में हो रही बढ़ोतरी से इलेक्ट्रिक उपकरणों मसलन स्विच, सॉकेट और स्विचगियर की मांग में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए पैनासोनिक को उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दरकार है और कंपनी ने कहा कि इसे देखते हुए ही नई फैक्टरी लगाने का फैसला लिया गया है। भारत में पैनासोनिक का उत्पादन आधार हरिद्वार, दमन और कच्छ में है, लेकिन दक्षिण में कोई फैक्टरी नहीं है, जहां मजबूत खरीद शक्ति और बढ़त की अच्छी संभावना है। श्रीसिटी की नई फैक्टरी इस इलाके की जरूरतें पूरी करेगी।

नई फैक्टरी साल 2021 में उत्पादन शुरू कर सकती है और वायरिंग उपकरणों के अलावा यहां धीरे-धीरे पंखे, स्विचगियर और इलेक्ट्रिकल वायर का उत्पादन शुरू होगा। पैनासोनिक मध्यम वर्ग को लक्षित कर उत्पादों का विस्तार करेगी।

आरबीआई करेगा बॉन्डों की विशेष खरीद-बिक्री

अनूप रॉय
मुंबई, 26 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सेकंडरी बाजार में एक और बॉन्ड खरीद एवं बिक्री का संचालन करेगा। आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वह 10,000 करोड़ रुपये के 10 वर्षीय बॉन्ड खरीदेगा, इसके साथ ही 2020 में परिपक्व हो रहे समान राशि तक के चार बॉन्डों की बिक्री करेगा।

केंद्रीय बैंक ने इसी तरह का परिचालन इस सप्ताह के शुरू में सोमवार को किया और अगला ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) अगले सोमवार को होगा। पिछली नीलामी में, आरबीआई ने 10 वर्षीय बॉन्डों का पूरा कोटा खरीदा, लेकिन अगले एक साल में परिपक्व हो रहे महज 6,825 करोड़ रुपये अल्पावधि बॉन्डों की बिक्री की।

पिछले सप्ताह पहले ओएमओ की घोषणा के बाद, 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 15 आधार अंक से ज्यादा गिर गया था। सोमवार को निर्णायक प्रतिफल 6.546 प्रतिशत पर था। गुरुवार को 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 6.58 प्रतिशत पर बंद हुआ। बॉन्ड डीलरों का कहना है कि दीर्घावधि प्रतिफल में कमी लाने के लिए केंद्रीय बैंक को लगातार इस तरह के ओएमओ पर ध्यान देना होगा, अन्यथा 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल चढ़कर फिर से 6.75 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगा, हालांकि अल्पावधि बॉन्ड प्रतिफल ज्यादा नहीं चढ़ा है। ऐसे ओएमओ के जरिये, आरबीआई एक वर्षीय और 10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल के बीच अंतर को दूर करने की कोशिश कर रहा है। यह अंतर बढ़कर 160 आधार अंक से ऊपर पहुंच गया था। दीर्घावधि प्रतिफल में नरमी लाने से सरकार को अतिरिक्त रकम सस्ती दर पर उधार लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा, 10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल में नरमी आने से राज्यों और कंपनियों के लिए उधारी लागत भी घटती है।

चूंकि कई बैंकों ने अपनी खुदरा उधारी दरें रीपो से जोड़ दी हैं, और अल्पावधि प्रतिफल बढ़ने से ऋण समान अंतर में महंगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रीपो में अब लंबे समय तक इजाफा होने की संभावना नहीं है।

सूचीबद्ध कराने की योजना टलने का रिलायंस रिटेल पर असर

सचिन मामबटा
मुंबई, 26 दिसंबर

खुदरा निवेश

- रिलायंस रिटेल के असूचीबद्ध शेयर का कारोबार 800 रुपये पर हुआ
- आरआईएल ने 400 रुपये के भीतर अदला-बदली की घोषणा की
- दस्तावेज में कहा गया है कि इसे सूचीबद्ध कराने की योजना नहीं
- असूचीबद्ध शेयरों की ट्रेडिंग को झटका

एक व्यवस्था की घोषणा के जरिये रिलायंस रिटेल के शेयरों में शायद ट्रेडिंग हो रही है और इस व्यवस्था के तहत इसके शेयर मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयरों से एक्सचेंज किए जाएंगे।

अदला-बदली (स्वैप) में उम्मीद से कम मूल्यांकन और सूचीबद्धता के फायदे की संभावना धूमिल होने का असर सेंटिमेंट पर पड़ा है। यह कहना है बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करने वाले एक असूचीबद्ध शेयर डीलर का।

असूचीबद्ध शेयरों के कोलकाता स्थित डीलर ने कहा कि रिलायंस रिटेल के शेयरों में 800 रुपये तक भाव पर ट्रेड हुए हैं, लेकिन नई व्यवस्था के जरिए कीमत 400 रुपये से कम होगी। इससे वॉल्यूम प्रभावित हुआ है। मुंबई के एक अन्य डीलर ने कहा कि इस शेयर के विक्रेता हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है क्योंकि मांगी गई कीमत विलय के जरिए मिलने वाली कीमत के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा है।

एक डीलर ने कहा, हर कोई सदमे में है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बाजार में विक्रेता हैं, लेकिन इस खबर के बाद कोई खरीदार नहीं है। इस कदम से जुड़े दस्तावेज के मुताबिक, यह व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि इसे सूचीबद्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

इसमें कहा गया है, कंपनी को उन कर्मचारियों से निकासी व नकदी का विकल्प मुहैया कराने के लिए अनुरोध मिल रहे हैं जिनके पास कंपनी की इक्विटी है, जिनमें इस शेयर को सूचीबद्ध कराया जाना शामिल है। स्टॉक एक्सचेंजों पर इसे सूचीबद्ध कराने की कंपनी की कोई योजना नहीं है।

कंपनी ने पहले अपनी खुदरा इकाई को अगले पांच साल में सूचीबद्ध कराने की बात कही थी। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया कि निवेशकों को रिलायंस रिटेल के चार शेयरों के बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर मिलेंगे।

स्वतंत्र विश्लेषक एस पी तुलस्यान ने कहा, बाजार चार लाख करोड़ रुपये का मूल्यांकन मानकर चल रहा था क्योंकि रिलायंस रिटेल का मूल्यांकन ग्रे मार्केट की कीमतों पर आधारित था। वॉल्यूम के लिहाज से इस क्षेत्र में सीमित ट्रेडिंग देखने को मिली थी। उनके मुताबिक, किसी कंपनी के मूल्यांकन का यह सही बैरोमीटर नहीं हो सकता, हालांकि ग्रे मार्केट में उम्मीद धराशायी होने से कुछ असर सूचीबद्ध शेयर की कीमत पर भी पड़ सकता है। मौजूदा अदला-बदली अनुपात इसका मूल्यांकन तीन लाख करोड़ रुपये से कम बैठता है।

उन्होंने कहा, इसने निश्चित तौर पर रिलायंस की शेयर कीमतों को झटका दिया है। गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर दो फीसदी टूटकर 1,515.4 रुपये का रह गया।

निफ्टी इंडेक्स की आय में होगी सुस्त बढ़ोतरी

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 26 दिसंबर

बढ़त के अनुमान में 100 आधार अंकों की संभावित कटौती के बावजूद निफ्टी इंडेक्स की आय साल 2020 में 15-16 फीसदी के दायरे में रह सकती है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम अनुमान करीब 26 फीसदी का है। यह कहना है क्रेडिट सुइस वेल्थ मैनेजमेंट के इंडिया इक्विटी शोध प्रमुख जितेंद्र गोहिल का, जिन्होंने विश्लेषक प्रेमल कामदार के साथ एक रिपोर्ट में ये बातें कही है।

> इस बढ़त का ज्यादातर हिस्सा वित्तीय कंपनियों की कम प्रावधान जरूरतों से आएगा

उनका मानना है कि इस बढ़त का ज्यादातर हिस्सा वित्तीय कंपनियों की कम प्रावधान जरूरतों से आएगा, जिसके बारे में उनका अनुमान है कि यह निफ्टी इंडेक्स की आय में 80 फीसदी से ज्यादा का योगदान कर सकता है। क्रेडिट सुइस के नोट में कहा गया है, मौजूदा टैरिफ बढ़ोतरी और अगले साल भी बढ़ोतरी की संभावना के साथ दूरसंचार क्षेत्र अपनी आय की रफ्तार बढ़ाने की स्थिति में पहुंच गया है। दूसरी ओर धातु व खनन कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र की आय में उतारचढ़ाव हो सकता है। उपभोक्ता कंपनियां पहले ही इस साल कर कटौती से लाभ हासिल कर चुकी हैं और उम्मीद है कि ये कंपनियां साल 2020 में उपभोक्ताओं के कम खर्च के माहौल के साथ बने रहने की खातिर लागत कटौती और मार्जिन संरक्षित करने में सक्षम होंगी।

गोहिल व कामदार को उम्मीद है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की आय एक अंक में बढ़ेगी, वहीं इंडस्ट्रियल व पूंजीगत सामान बनाने वाली कंपनियां आय में तेज गिरावट का सामना कर सकती हैं।

नवी टेक्नोलॉजिज की हुई मावेनहाइव

युवराज मलिक
बेंगलूरु, 26 दिसंबर

सचिन बंसल का दांव

- सचिन बंसल की स्वामित्व वाली कंपनी है नवी टेक्नोलॉजिज
- इस अधिग्रहण से नवी की प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद विकास दक्षता दमदार होगी

सचिन बंसल के स्वामित्व वाली कंपनी नवी टेक्नोलॉजिज ने प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म मावेनहाइव का अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण से नवी टेक्नोलॉजिज की प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद विकास दक्षता दमदार होगी और स्टार्टअप के लिए उसकी पेशकश बेहतर होगी।

करीब सात साल पुरानी कंपनी मावेनहाइव ग्राहकों को उत्पाद विकास में मदद करेगी जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, ऐप डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं। मावेनहाइव फ्लिकार्ट, गोजेक, ग्रासहूपर, स्क्रिपबॉक्स आदि कंपनियों को अपनी सेवाएं दे चुकी है।

नवी टेक्नोलॉजिज के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बंसल ने एक बयान में कहा, 'इस अधिग्रहण से नवी की प्रौद्योगिकी दक्षता बेहतर होगी।' दोनों पक्षों में से किसी ने भी सौदे के आकार का खुलासा नहीं किया है लेकिन मावेनहाइव के दो संस्थापक और 40 अन्य टीम सदस्य बंसल की स्वामित्व वाली कंपनी में शामिल हो चुके हैं।

मावेनहाइव की स्थापना भाविन जाविया और आनंद कृष्णन ने 2012 में की थी। जाविया को विभिन्न कंपनियों में 15 वर्षों के आईटी परामर्श का अनुभव प्राप्त है जहां उन्होंने विभिन्न टीमों का नेतृत्व किया और कारोबारियों के लिए महत्त्वपूर्ण ऐप्लिकेशन तैयार करने में मदद की। कृष्णन ने कई बड़े ऐप्लिकेशन तैयार किए और उनका वितरण किया। दोनों ने एक वैश्विक सॉफ्टवेयर डिलिवरी एवं परामर्श फर्म थॉटवर्क्स में लंबे समय तक काम किया है।

जाविया ने कहा, 'हम सचिन औ नवी के साथ काम शुरू करने के लिए काफी उत्साहित हैं।' उन्होंने कहा, 'फ्लिपकार्ट में उन्होंने जिस तरह का संगठन तैयार किया उससे हम चकित थे। इसलिए जब योगी कुलकर्णी (फ्लिपकार्ट के पूर्व प्रधान आर्किटेक्ट और नवी में इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष) ने हमें इस अवसर की जानकारी दी तो हम उनकी यात्रा के अगले दौर में शामिल होने को लेकर काफी उत्साहित थे।'

गिग वर्कर्स को मिलेगी सस्ती स्वास्थ्य सेवा

सोमेश झा
नई दिल्ली, 26 दिसंबर

गिग इकॉनमी से जुड़ी कंपनियों पर संभवत: अपने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवर में अंशदान के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। इसकी जगह सरकार गिग इकॉनमी में काम करनेवाले कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अस्पतालों व डिस्पेंसरी में सब्सिडी वाली दरों पर सस्ती चिकित्सा सेवा मुहैया कराने पर विचार कर रही है।

इससे गिग इकॉनमी से जुड़ी कंपनियों को राहत मिल सकती है क्योंकि उन्हें अपने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा की लागत को वहन नहीं करना होगा।

पिछले महीने सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया था। इस विधेयक में गिग इकॉनमी में काम करने वाले कर्मचारियों को भारत में पहली बार सामाजिक सुरक्षा कवर देने का प्रस्ताव है। विधेयक में कहा गया है कि सरकार ईएसआईसी के तहत गिग कर्मचारियों को लाने के लिए एक योजना पेश करेगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'गिग कर्मचारियों को इलाज की सुविधा न्यूनतम उपभोग शुल्क के आधार पर देने की योजना है, न कि कर्मचारियों से अंशदान लेकर।'

सामान्यतया उबर, ओला के चालकों, जोमैटो और स्विगी के डिलिवरी पहुंचाने वालों जैसे शेयरिंग अर्थव्यवस्था के कर्मचारियों आदि को गिग वर्कर्स कहा जाता है। यह नौकरियां तकनीकी प्लेटफॉर्म से संचालित होती हैं, जहां कर्मचारी किसी संगठन से बंधा नहीं होता है और वह अपनी इच्छा के मुताबिक काम करने या न करने का विकल्प चुन सकता है।

अधिकारी ने बताया कि गिग इकॉनमी में काम करने वाले ईएसआईसी अस्पताल व डिस्पेंसरी में इलाज के लिए जा सकेंगे, जहां केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत सस्ती चिकित्सा सेवा मिलेगी। सीजीएचएस सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, मौजूदा और पूर्व सांसदों, न्यायाधीशों व अन्य के लिए है।

अधिकारी ने कहा, 'ईएसआईसी ईएसआईसी के तहत 21,000 रुपये प्रति महीने तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मेडिकल, कैश, मातृत्व, अक्षमता और कर्मचारी के आश्रितों को लाभ मिलता है।मौजूदा ईएसआईसी कानून उन फैक्टरियों पर लागू होता है, जहां 10 या इससे ज्यादा कर्मचारी हैं और यह दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, सिनेमाघरों और सड़क परिवहन निगमों पर भी लागू होता है। कर्मचारी व नियोक्ता दोनों मिलकर कर्मचारी के वेतन का 4 प्रतिशत मासिक भुगतान ईएसआईसी में करते हैं।

इसमें देश भर में करीब 160 अस्पताल और 1,500 डिस्पेंसरी को शामिल किया गया है। जब सरकार ने मसौदा सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक सितंबर में जारी किया था, कुछ कंपनियों व विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि क्या गिग इकॉनमी में काम करने वालों के लिए भी कंपनियों को अंशदान करना होगा या नहीं।

उनका तर्क था कि अगर गिग इकॉनमी को किसी तरह से नियमन के दायरे में लाने से उनकी ओर से कर्मचारियों को दी जा रही स्वतंत्रता प्रभावित होगी और इसका कंपनियों पर असर पड़ेगा।

उबर, ओला के चालकों, जोमैटो और स्विगी के डिलिवरी पहुंचाने वाले कर्मचारियों आदि को गिग वर्कर्स कहा जाता है

क्या है सामाजिक सुरक्षा विधेयक में

- गिग वर्कर्स में वे कर्मचारी शामिल हैं, जो एक काम करने की व्यवस्था में हिस्सा लेते हैं या काम करते हैं और परंपरागत नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के बाहर की गतिविधियों से पैसे कमाते हैं
- गिग वर्कर्स को असंगठित कर्मचारी माना गया है, उनके लिए भविष्य निधि में अंशदान की जरूरत नहीं होती
- सरकार ऐसे कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत लाभ देने के लिए योजना तैयार करेगी
- सरकार गिग वर्कर्स के नियोक्ताओं से अंशदान करने को नहीं कहेगी, जैसा अन्य मामलों में किया जाता है
- कर्मचारियों को न्यूनतम उपभोग शुल्क के आधार पर भुगतान करना होगा
- ईएसआईसी अस्पतालों व डिस्पेंसरी में केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना की दरों पर गिग वर्कर्स को मिल सकेगी इलाज की सुविधा

कंपनियों ने मांग घटने से कम किया उत्पादन

पृष्ठ 1 का शेष

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के मुख्य कार्याधिकारी वीजी कन्नन ने कहा, 'मांग कम होने से कई कंपनियों ने अपना उत्पादन घटा दिया है। इससे उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरत भी कम हो गई है। इसके साथ ही जिनके पास नकदी है वे पुराने कर्ज को चुकाना पसंद कर रहे हैं।' इक्रा ने कहा, 'सेवा क्षेत्र में एनबीएफसी की उधारी बढ़ी है। हालांकि कारोबार से जुड़ी उधारी और अन्य सेवाओं (आवास वित्त आदि) में उधारी मांग कम हुई है। खुदरा ऋण के हिस्से में वृद्धि मुख्य रूप से बैंकों द्वारा एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो खरीदने की वजह से हुई है।' 6 दिसंबर, 2019 तक जमा में वृद्धि बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपये रह गई जो वित्त वर्ष 2019 की समान अवधि में 4.6 लाख करोड़ रुपये थी। इक्रा के अनुसार, कुल जमा आधार सालाना आधार पर 10.3 फीसदी बढ़कर 6 दिसंबर, 2019 तक बढ़कर 131.1 लाख करोड़ रुपये रहा। तंत्र में मुद्रा के चलन में कमी, डेट म्युचुअल फंडों के प्रबंधन वाली संपत्तियों में कम वृद्धि और कंपनियों के पास अधिक नकदी से जमा बढ़ी है।

राजन ने पहले ही दे दी थी संकट की चेतावनी

पृष्ठ 1 का शेष

प्रणव मुखर्जी: जब भारत ने 2010 के दशक में प्रवेश किया था तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कमान प्रणव मुखर्जी के हाथों में थी। उन्होंने ही भारत को वित्तीय संकट से उबारा था। वित्त मंत्री के तौर पर यह उनका तीसरा कार्यकाल था और इस दौरान उन्हें भारी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। इसके कई कारण थे। माना जाता है कि राजकोषीय प्रोत्साहन को पर्याप्त तेजी से वापस नहीं लिया गया जिससे उत्पादक क्षमता बढ़ती मांग के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई और राजकोषीय मोर्चे पर स्थिति खराब हो गई। दूसरी वजह यह थी कि उस दौरान वित्त मंत्रालय ने कई कदम उठाए जिनसे निवेशक खासकर विदेशी निवेशक अलग-थलग पड़ गए। इनमें आम बजट में पिछली तारीख से कर में बदलाव सबसे अहम है। वोडाफोन के उच्चतम न्यायालय में मामला जीतने के बाद ऐसा किया गया।

कई बार ऐसे मौके आए जब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष से भी सलाह लेना मुनासिब नहीं समझा। पिछली तारीख से कर में संशोधन इनमें से एक था। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था की सुस्ती और नीतिगत पंगुता के दौर को याद करें तो मुखर्जी का चेहरा बरबस याद आता है। जब वह राष्ट्रपति बने तो कई लोगों ने राहत की सांस ली।

रघुराम राजन: अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रघुराम राजन के बारे में मशहूर है कि उन्होंने पहले ही आर्थिक संकट की चेतावनी दे दी थी। उन्हें 2012 में मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगले ही वर्ष उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाकर मुंबई भेज दिया गया। अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में ही उन्होंने अपनी बेबाकी से सुर्खियां बटोरी। उस समय देश में आर्थिक मोर्चे पर निराशा का भाव था और ऐसे में वह मौद्रिक मोर्चे पर नई सोच और विशेषज्ञता का वादा कर रहे थे। उनके कार्यकाल में भारत ने केंद्रीय बैंक में मुद्रास्फीति के लक्ष्य के क्रियान्वयन के लिए अहम कदम उठाया। इससे पहले के वर्षों में महंगाई चरम पर थी। इस दशक के उत्तरार्द्ध में महंगाई ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से लगातार कम रही। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक ढांचागत बदलाव के अनुरूप नहीं ढली है और वह कंपनियों की कमाई की उम्मीदों और ग्रामीण आय जैसे कारकों से प्रभावित होती है। लेकिन राजन के कार्यकाल में देश को यह अहसास भी हुआ कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र फंसे कर्ज की भारी समस्या से जूझ रहा है। यह समस्या वित्तीय संकट के वर्षों से चली आ रही थी जिससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता और निजी निवेश की रफ्तार सुस्त पड़ रही थी।

मुकेश अंबानी: 2014 में सरकार बदलने के बाद फंसे कर्ज की समस्या भी तेज हो गई और निजी निवेश पीछे छूटता चला गया। फिर भी कुछ बड़े औद्योगिक समूह खासकर अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निवेश जारी रखा। इसकी वजह यह थी कि उसे पेट्रोकेमिकल कारोबार से लगातार भारी मुनाफा हो रहा था। 2000 के दशक में मुकेश अंबानी की महत्त्वाकांक्षाएं भाई अनिल के साथ चल रहे विवादों के कारण परवान नहीं चढ़ पाईं लेकिन 2010 के दशक में उन्होंने इस दौड़ में निर्णायक बढ़त बना ली।

जियो ने आधिकारिक शुरुआत से पहले ही अपना कारोबार काफी फैला लिया था। इसके साथ ही रिलायंस ने यह संकेत भी दे दिया कि वह पेट्रोकेमिकल की पुरानी दुनिया से निकलकर दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के नए दौर में जाना चाहती है। रिलायंस ने समाजवाद के दौर में शुरुआत की और फिर उदारीकरण के बाद सस्ते संसाधनों के जमाने में अपना कारोबार फैलाया। 2010 के दशक में उसने जियो पर बड़ा दांव लगाकर देश में नई आर्थिक क्रांति का संकेत दे दिया।

विजय शेखर शर्मा: नई अर्थव्यवस्था के नए भारत में नए उद्यमी भी आए। 2010 के दशक में शर्मा से बेहतर दूसरा प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। वह वॉलेट कंपनी पेटीएम के सर्वेसर्वा हैं। मोदी सरकार ने जब नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी तो उस समय लगा कि केवल शर्मा ही इसके लिए तैयार बैठे थे। नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान में हुई भारी बढ़ोतरी से पेटीएम को काफी फायदा हुआ।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले शर्मा पेशे से इंजीनियर हैं और वह पिछली पीढ़ियों के उद्यमियों से एकदम अलग हैं। नोटबंदी के बाद पेटीएम की वर्षांत पार्टी में उन्होंने जिस अंदाज में अपने साथियों की हौसला अफजाई की, उसका वीडियो वायरल हो गया था। हालांकि पेटीएम अब भी नुकसान में चल रही है। पिछले वित्त वर्ष में उसे 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था लेकिन उसे अब भी अरबों डॉलर का फंड मिल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि निवेशकों का भरोसा अब भी शर्मा पर बना हुआ है।

इनमें से कम से कम तीन हस्तियां अगले दशक में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका में होंगी। क्या अंबानी जियो को देश में दूरसंचार का स्वाभाविक विकल्प बनाने में सफल होंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को क्या फायदा होगा? क्या शर्मा जैसे युवा उद्यमी आगे भी वैश्विक निवेशकों का भरोसा कायम रख पाएंगे और क्या डिजिटल इंडिया पर उनका दांव सफल रहेगा? सबसे अहम सवाल यह है कि मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर कैसे निकालेंगे जिसकी सुस्ती की मुख्य वजह घरेलू कारक हैं? इसका उत्तर अगले दशक में छिपा है।

जीएसटी दाखिल न करने वालों की जब्त हो सकती है संपत्ति

कर अधिकारी जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वालों के बैंक खातों सहित उनकी संपत्तियां जब्त कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक जीएसटी आयुक्त केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 83 के मुताबिक अनंतिम रूप से संपत्ति जब्त कर सकता है।

एसओपी के मुताबिक इसके साथ ही वह एक विशेष अवधि तक रिटर्न दाखिल करने का काम पूरा नहीं करने पर पंजीकरण भी रद्द कर सकता है। यह खास अवधि कितनी होगी, इस पर अभी फैसला होना बाकी है।

इस धारा के तहत आयुक्त करदाता के बैंक खाते सहित उसकी कोई भी संपत्ति जब्त कर सकता है। इसके लिए उसे एक विशेष फॉर्म पर आदेश पारित करना होगा, जिसमें जब्त की जाने वाली संपत्ति का ब्योरा होगा। बहरहाल विशेषज्ञों ने कहा कि जीएसटी के पहले राज्य स्तर के मूल्यवर्धित कर के दौरान बमुश्किल ही कोई पंजीकरण रद्द किया गया। एक साल से ज्यादा समय तक रिटर्न दाखिल न करने पर कर अधिकारी पंजीकरण निष्क्रिय कर देते थे। *बीएस*

बीएस सूडोकू 3623 | परिणाम संख्या 3622

			2	6		5		8
2	9	1	8			4		
		2	1				3	5
				5				
4	6				9	8		
		8			3	1	5	9
1		4		9	8			

7	8	6	4	3	1	2	5	9
5	2	1	6	9	8	4	3	7
4	9	3	2	7	5	8	6	1
3	7	2	5	8	9	1	4	6
1	4	9	7	6	3	5	8	2
8	6	5	1	2	4	7	9	3
2	5	7	9	4	6	3	1	8
6	1	8	3	5	2	9	7	4
9	3	4	8	1	7	6	2	5

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम
★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2145/2150, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4500/4525, तिल सफेद 9500/9700, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1670,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2150/2160, गेहूं शरबती 2800/2900, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1435, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1515, फ्लैक 1445, डीएमओ 1055, टरपीन लैस बोल्ड 1550

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1150/1280, खुरपा 1150/1180,चाकू 1150/1265, रसकट 910/930, शक्कर 1300/1330, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3385, सिहोरा 3255, बुंदकी 3290, बुढ़ाना 3370,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1180/1230, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4650, खल: सरसों 2350/2450, बिनौला 2550/2650, चना छिलका 2050/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2200/2210, मक्की 2250/2275, बाजरा 1920/1925, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4790/4800,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2075/2125, ग्वार 3800/3850, जौ 2080/2090,

जोधपुर
गेहूं 2075/2100, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7550/7650, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4250/4350, काबली चना 5000/6000, मूंग 6400/6600,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)132, राइसब्रान (अखाद्य) 129, खल सरसों 2150, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1380,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7200/8200, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8500/9500, दाल मसूर 5800/6200, चनादाल 5300/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5550/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4150/4250,चावल 1509 सेला 5150/5250, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4000/4030, हरियाणा 3980/4000, राजस्थान 3950/4000, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2550/2650, सरसों खल 2240/2250,

फाजिल्का
गेहूं 2200/2210, सरसों 4525/4550 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4000/4050, कपास देशी 5000/5100, कपास नरमा (क्विं.) 5300/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2600/2650,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2190/2200, चावल परमल कच्चा 2500/2550, से ला 2400/2425, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2475/2500, दाल उड़द छिलका 8800/10600, चना देशी 5150/5250, दाल चना 5400/5600, काबली चना 5100/6000, राजमां चित्रा पुणे 7000/8400, चीन 7500/8100,

करनाल
गेहूं दड़ा 2180/2190, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 3900/3825, जौ 1775/1780, सरसों 4250/4300, मूंग 6600/6700, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1050/1070, मैदा 1150/1170, देशी घी (एक ली/जार) 380/480, रिफाइंड (टीन) 1510/1540,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4300/4350, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 9450/9500, गेहूं 2150/2200, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 267

चेत जाएं सरकारी बैंक

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कई वर्ष बाद बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट 'ट्रेंड ऐंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2018-19' यह बताती है कि बैंकों की ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों में कमी आई है और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट भी थमी है। यही कारण है कि वर्ष 2011-12 के बाद पहली बार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समेकित बैलेंस शीट में सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा बैंकिंग जगत का वित्तीय प्रदर्शन भी सुधरा और तीन वर्ष के अंतराल के बाद सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में शुद्ध मुनाफा कमाया।

परंतु सरकारी बैंकों के लिए अभी भी चिंतित होने की पर्याप्त वजह है। न केवल फंसे हुए कर्ज (एनपीए) का ज्यादा हिस्सा उनके पास है बल्कि वे निजी बैंकों के हाथों तेजी से कारोबार भी गंवा रहे हैं। उदाहरण के लिए समीक्षा अवधि के दौरान सावधि जमा में हुई वृद्धि में निजी बैंकों की हिस्सेदारी करीब 77 प्रतिशत रही। निजी बैंकों में इसका स्तर 2011-15 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2016-19 में 81 फीसदी हो गया। बैंकिंग परिसंपत्तियों में एक तिहाई से भी कम भागीदारी के बावजूद निजी बैंक वर्ष 2018-19 में ऋण में हुई वृद्धि में से 69 फीसदी के हिस्सेदार रहे। कुल बकाये में भी निजी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस बदलाव की वजह समझना कठिन नहीं है। निजी क्षेत्र के बैंक अपेक्षाकृत किफायती हैं और वे बेहतर सेवाओं और आकर्षक जमा दर के साथ ज्यादा राशि जुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च जमा दर उनके मार्जिन पर असर नहीं डाल रही है। निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंकों की तुलना में अधिक विशुद्ध ब्याज मार्जिन रखते हैं। यहां भी दोनों में बड़ा अंतर है। वर्ष के दौरान सामने आए धोखाधड़ी के मामलों में से 90 प्रतिशत सरकारी बैंकों में हुए। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्याप्त आंतरिक प्रक्रिया के अभाव और प्रक्रियात्मक जोखिम से निपटने में सक्षम लोगों और तंत्र की अनुपस्थिति से ऐसा हुआ।

निजी बैंकों की बढ़ती हिस्सेदारी का सिलसिला आगे जारी रहेगा और इसकी कई वजह हैं। बढ़ा हुआ एनपीए सरकारी बैंकों के लिए बड़ी बाधा बना रहेगा और सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अनंत काल तक इन बैंकों में भारी-भरकम पूंजी निवेश करती रहे। दूसरी ओर, भले ही कुछ निजी बैंकों में समस्याएं रही हैं लेकिन वे अभी भी बेहतर स्थिति में हैं। वहां शीर्ष प्रबंधन आसानी से बदल सकता है और निजी बैंक पूंजी जुटाने तथा बैलेंस शीट विस्तार के मामले में भी बेहतर स्थिति में हैं।

बहरहाल, यह बात ध्यान देने वाली है कि निजी बैंकों के पक्ष में हो रहा यह बदलाव सरकारी बैंकों के मूल्यांकन को भी कम करेगा। व्यापक स्तर पर देखें तो सरकारी बैंकों की कमियां तंत्र में ऋण की उपलब्धता को भी प्रभावित करेंगी और आर्थिक वृद्धि को बाधित करेंगी। ऐसे में सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह संचालन संबंधी सुधार लागू करके सरकारी बैंकों को निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा के लायक बनाए। भारत से जुड़ी अपनी ताजा रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सरकारी बैंकों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उसका यह कहना सही है कि सुधारों के अभाव में विलय से जरूरी मुद्दे हल नहीं होंगे और बड़े और कमजोर बैंक सामने आने की आशंका बढ़ जाएगी। विलय होने से मूल कारोबार से भी ध्यान हट सकता है और ऋण क्षमता प्रभावित हो सकती है। सरकार (पढ़ें करदाताओं) और सरकारी बैंकों के हाथ से समय बहुत तेजी से निकल रहा है।

(अस्वीकरण: कोटक परिवार के नियंत्रण वाली संस्थाओं की बिज़नेस स्टैंडर्ड में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है।)

अजय मोहंती

भारत के लिए बांग्लादेश की सामरिक अहमियत

हमारे पूर्वी समुद्री तट पर एक अहम देश बांग्लादेश है। भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भारत के हितों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बता रहे हैं **प्रेमवीर दास**

भारत और बांग्लादेश वर्ष 1971 से लंबी दूरी तय कर चुके हैं। दोनों देशों के संबंध शेख मुजीबुर्रहमान के समय में अत्यंत मधुर थे। लेकिन जिया-उर-रहमान और उनकी पत्नी बेगम जिया के कार्यकाल में संबंध खराब हुए। हालांकि अब मुजीब की बेटी शेख हसीना के शासनकाल में संबंध फिर से प्रगाढ़ हो रहे हैं। इस तरह दोनों देशों के बीच संबंधों ने एक लंबी दूरी तय की है, जिनमें कई उतार-चढ़ाव आए हैं।

अब दोनों देशों के संबंध बेहतर हो रहे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने की हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए कि दोनों देशों के संबंधों में यह बेहतरी लगातार जारी रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल के महीनों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित भारत की आकांक्षाओं पर कई बार जोर दे चुके हैं। बांग्लादेश इसी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, जिसे निश्चित रूप से प्रमुखता में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में हमें हाल की घटनाओं के नतीजों को देखना चाहिए, जो बांग्लादेश के दो वरिष्ठ मंत्रियों के हमारे देश की यात्रा रद्द करने का नतीजा हैं।

पिछले कई दशकों से हमारे सीमा विवाद के मुद्दों का इतिहास हर कोई जानता है और अब समुद्री सीमा के सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान के बारे में ज्यादातर भारतीयों को नहीं पता है। दोनों देशों के बीच कई वर्षों से न्यू मूर द्वीप को लेकर विवाद रहा है। यह द्वीप उच्च ज्वार में पानी में डूब गया था, लेकिन पानी उतरने पर काफी स्पष्टता से दिखाई देने लगा। बांग्लादेश ने इस द्वीप पर अपना दावा किया और इससे अपनी समुद्री सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्धारित किया। वहीं भारत ने कहा कि वह उसके क्षेत्र में आता है। दोनों के दावों के पीछे यह आकलन था कि न्यू मूर के आसपास समुद्र में तेल एवं गैस के भंडार हैं।

एक समय भारत ने इस द्वीप के आसपास अपने नौसैनिक और एक जहाज तैनात कर दिया था। दोनों देशों के बीच काफी कड़वाहट और कटुता जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यह मसला 2014 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिये सुलझा। इसमें भारत में न्यू मूर द्वीप और उस करीब 80 फीसदी पानी पर अपना दावा छोड़ दिया, जिसका उसने दावा किया था। इस तरह दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंधों के बीच आने वाली एक बाधा दूर हो गई, इसलिए अब दोनों देशों के बीच भू-सीमा और समुद्री सीमा से जुड़े मुद्दों का समाधान हो गया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे हितों के लिए बांग्लादेश महत्त्वपूर्ण क्यों है? बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में करीब 600 मील दूरी पर स्थित है, जहां चटगांव और कॉक्स बाजार जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं। ऐसे में बांग्लादेश हमारी पूर्व समुद्री सीमा पर एक महत्त्वपूर्ण तटीय देश है। बांग्लादेश और म्यांमार के बंदरगाह बुनियादी ढांचा विकास के रूप में चीन के साथ सुरक्षा संबंध हैं। इसमें दोनों को सैन्य एवं नौसैन्य साजोसामान की आपूर्ति भी शामिल की जानी चाहिए, जिसमें दो सबमरीन प्रमुख हैं। चीन के जंगी जहाज बहुधा चटगांव आते-जाते रहे हैं। अगर यह संबंध आगे और मजबूत होता है तो यह भारत के लिए नुकसानदेह होगा।

बांग्लादेश चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव का समर्थक है। चीन लंबे और दुरुह मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते से बचने के लिए अपने युन्नान प्रांत को हिंद महासागर से जोड़ना चाहता है। उसे इसके लिए बांग्लादेश के चटगांव तक पहुंचने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो हमें चीन की नौसेना और जहाजों की बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीपसमूह के आसपास मौजूदगी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा सकारात्मक माहौल ने सभी संभावित नकारात्मक कारकों को पीछे धकेल दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए, जिससे स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाए।

नौसेना प्रमुख ने इस महीने की शुरुआत में खुलासा किया था कि चीनी अनुसंधान जहाज हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुस आए और उन्हें जाने के लिए कहना पड़ा। ऐसी घुसपैठ पहली बार नहीं हुई है। ये जहाज समुद्र के तल की संभावनाओं और सोनार स्थितियों की जांच करते हैं, जो सबमरीन के अनुकूलतम परिचालन में मददगार हैं और स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं। इसके अलावा अन्य के समुद्री क्षेत्र में विदेशी जंगी जहाजों की तैनाती के लिए पहले से मंजूरी की जरूरत होती है। इसका अपवाद केवल 'इनोसेंट पैसिज' है। इनोसेंट पैसिज अंतरराष्ट्रीय कानून की शब्दावली है जिसमें अगर कोई जहाज दूसरे देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है तो वह उस देश के क्षेत्र से गुजर सकता है।

चीनियों ने बार-बार इस जरूरत की अनदेखी की है। उन्होंने दक्षिणी चीनी सागर में अंतरराष्ट्रीय कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन किया है, जहां फिलिपींस और वियतनाम जैसे छोटे देश बलपूर्वक उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमारे हित क्षेत्र में ऐसा करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। बंगाल की खाड़ी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है, जिसकी हमारी रणनीतिक एवं सुरक्षा प्राथमिकताओं में ऊंचा स्थान है।

ऐसी अनधिकृत घुसपैठ को छोड़ भी दें तो सोमालिया के समुद्री डाकुओं का खतरा बढ़ने के बाद चीन की नौसेना की मौजूदगी हिंद महासागर में 2008 के बाद तेजी से बढ़ी है। उनका बेस पाकिस्तान (ग्वादर) और जिबूती (अफ्रीका) में है। वे दोनों जगह सेना तैनात कर सकते हैं। वे तेल भरने वाले जहाज समेत चार से पांच जहाज अमूमन हिंद महासागर क्षेत्र में रखते हैं। इसके अलावा चीन सेशल्स जैसे द्वीपीय क्षेत्रों में मौजूदगी कायम करने की कोशिश कर रहा है। उसने श्रीलंका (हंबनटोटा और कोलंबो) और म्यांमार में बंदरगाह के विकास में अहम योगदान दिया है।

इसलिए भारत के हितों के लिए बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अहम हैं। अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश प्रत्येक आर्थिक और सामाजिक पैमाने पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इनमें से कई में वह भारत से भी आगे है। दोनों देशों के बीच असहमति के क्षेत्र भी बहुत कम हैं।

इसी पृष्ठभूमि में हमें हाल के घटनाक्रम को देखना चाहिए। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश को हिंदू अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वाला कहने से बांग्लादेश में अच्छा संदेश नहीं गया है। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि उसने अपना मौजूदा रुख ही दोहराया है। अच्छी बात यह है कि शेख हसीना ने खुद कोई टिप्पणी नहीं की। यह बताता है कि वह भारत के साथ संबंधों को कितनी अहमियत देती हैं। हालांकि बड़े मंत्रियों के दौरों को रद्द कर वांछित 'संदेश' दे दिया गया।

उम्मीद है कि इनसे बयानबाजी को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित और भारत के लिए महत्त्वपूर्ण दर्जनों देशों में बांग्लादेश को सबसे शीर्ष पर रखा जाना चाहिए। भारत के नजदीकी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश ही एकमात्र ऐसा देश है, जो 'दोस्त' कहलाने लायक है। अगर इस दर्जे में बदलाव हुआ तो यह हमारे हितों के लिए मददगार नहीं होगा।

(लेखक पूर्वी नौसेना कमान के पूर्व कमांडर इन चीफ हैं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं।)

निकाय अफसरों और पार्षदों पर कितना चलेगा अदालत का डंडा

अदालती आईना

एम जे एंटनी

बड़ा सवाल यह है कि क्या नियामकों में इतना साहस होगा कि वे शहरों के नामियों-गिरामियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोग चला सकें

देश में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां पानी की आपूर्ति या सीवरेज प्रवाह की संतोषजनक व्यवस्था हो। नगरपालिकाओं के अधिकारी आमतौर पर आम नागरिकों की शिकायतों के प्रति असंवेदनशील होते हैं और कभी कोई आवश्यक कदम उठाने में शीघ्रता नहीं दिखाते। यहां तक कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं और पर्यावरण संबंधी कानून इसलिए नहीं लागू किए जाते हैं क्योंकि ऐसे मामलों में कहीं न कहीं स्थानीय बाहुबली शामिल होते हैं और कानूनी प्रक्रिया का क्या नतीजा निकलेगा, यह तय नहीं होता। परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नगरपालिका पार्षदों और नगर निगमों के प्रमुख अधिकारियों पर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निर्णय कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बेंगलूरु तथा अन्य नगरपालिकाओं के सात आयुक्तों (जो अलग-अलग समय पर पद स्थापित रहे) के बीच 14 वर्ष से चली आ रही कानूनी लड़ाई में दिया गया। यह मामला था कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बी हीरा नाइक के बीच का।

यह निर्णय भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कंपनी शब्द की व्याख्या की गई है और इसके दायरे का विस्तार करते हुए वैधानिक संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। अदालत ने जोर देकर कहा कि नगर निगम के सरकारी विभाग होने की दलील दी जाती है लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि यह एक कॉर्पोरेट संस्थान है। चूंकि धारा 47 के तहत सभी निगम संस्थान कंपनी की परिभाषा के अधीन आते हैं इसलिए नगर परिषद भी इस दायरे में शामिल हैं। ऐसे में हर उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है जो अपराध घटित होते वक्त प्रभारी रहा हो और कंपनी के कारोबारी आचरण के लिए जिम्मेदार रहा हो। सजा से बचने के लिए उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि अपराध बिना उसकी जानकारी के हुआ या उसने अपनी तरफ से उचित सतर्कता बरती थी। जाहिर है जो पद पर रहे हों उनके लिए इसे साबित करने का बड़ा बोझ था। नगर पार्षदों की बात करें तो अब उनकी जवाबदेही कंपनी अधिनियम तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के तहत निदेशकों की जवाबदेही से अधिक है।

उच्च न्यायालय ने इन अधिकारियों पर अभियोग समाप्त करते हुए कहा कि वे विभागों के प्रमुख थे, न कि किसी कंपनी के कार्याधिकारी। ऐसे में अभियोजन को सरकार की मंजूरी भी आवश्यक थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय गलत था और इन पर कार्रवाई के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। बोर्ड ने आरोपित आयुक्तों को उपचारित सीवेज छोड़ने की मंजूरी प्रदान की थी जबकि यह 2006 में समाप्त हो चुका था और जिसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। वे निरंतर इस अनुपचारित सीवेज अवशिष्ट को तालाबों, झीलों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मिलने दे रहे थे। इस निर्णय के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह अधिकार मिला है कि वे जल एवं वायु संरक्षण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अभियोग चला सकें। कानून में अपराधों की सूची का ब्योरा भी पेश किया गया है। संक्षेप में कहें तो किसी व्यक्ति को जानते-बूझते कोई विषाक्त या प्रदूषक तत्त्व किसी जल धारा, कुएं, सीवर या जमीन में नहीं मिलने देना चाहिए। जो भी इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे अधिकतम छह वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

हाल के दिनों में अदालत पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों में कड़े आदेश सुनाती रही है। दो सप्ताह पहले दिए एक आदेश में उसने दिल्ली के निकट नोएडा के प्राधिकारियों को आदेश दिया कि एक गांव की जल धाराओं का पुनरुद्धार करें, उनका रखरखाव करें और उन्हें संरक्षण प्रदान करें। जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय के इस मामले में परंपरागत जल स्रोतों को औद्योगिक इकाइयों के फायदे के लिए पाटा जा रहा था।

इससे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हो रहा था। आम लोगों ने पहले भी जनहित याचिकाएं लगाई हैं। इनमें सबसे पहला है सन 1980 का रतलाम नगर निगम मामले का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के रतलाम नगर निगम को एक स्थान की साफ-सफाई कराने का आदेश देते हुए कहा था कि बजट की बाधा किसी नगर निगम द्वारा सफाई जैसे बुनियादी काम की अनदेखी करने का बहाना नहीं हो सकती। उक्त फैसला पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन रतलाम की यात्रा करने पर पता चल जाता है कि उस फैसले का जमीनी अमल न के बराबर हो रहा है। उसके बाद आया एम सी मेहता का मामला जिसमें अदालत अभी भी आदेश जारी कर रही है। सन 1996 में एमआईटी से स्नातक करने वाली पहली महिला इंजीनियर अल्मित्रा पटेल ठोस कचरे को लेकर अदालत गईं। साल दर साल आए अदालती आदेशों के बावजूद हालात और खराब ही हुए हैं। हाल में सरकार ने इस विषय पर 850 पृष्ठों का एक शपथ-पत्र दिया है। न्यायाधीशों ने कहा कि कागजों का यह बंडल अपने आप में ठोस कचरा है।

अब तक प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सबसे प्रमुख कारक सामाजिक कदम और क्षतिपूर्ति के होते थे। कर्नाटक का फैसला प्रदूषण बोर्डों को यह अधिकार देता है कि वे नगर निकायों के अधिकारियों के खिलाफ कदम उठा सकें। जनहित याचिकाओं में दिए जाने वाले निर्णयों की तुलना में आपराधिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी साबित होगी। बहरहाल, बड़ा सवाल यह है कि क्या नियामकों में इतना साहस होगा कि वे शहरों के नामियों-गिरामियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोग चला सकें।

कानाफूसी

गोवंश सुधार

मध्य प्रदेश के गोपालकों के पास अब अवसर है कि वे अपनी गायों के लिए बेहतर साथी तलाश कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने 200 से अधिक उन्नत नस्ल के सांडों का डेटाबेस तैयार किया है। इस डेटाबेस में उनके बारे में सूचनाओं को अलग-अलग खाकों में बांटा गया है। इनमें पहली जानकारी उनकी नस्ल को लेकर है। दूसरी श्रेणी में उस नस्ल की गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता तथा दूध में वसा की मात्रा है और तीसरी जानकारी बीमारियों के बारे में है। विभाग का कहना है कि इस डायरेक्टरी को नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाएगा और इसे इंटरनेट पर भी डाला जाएगा ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।

नए वर्ष का तोहफा

महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है। प्रदेश की नई सरकार ने न केवल क्रिसमस के अवसर पर होटलों को सुबह पांच बजे तक खुला रखने की इजाजत दी बल्कि नए वर्ष पर भी होटलों को इसी तरह खुला रखने की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वादा किया है कि आने वाले दिनों में होटलों को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत होगी और यह मुंबई को वैश्विक शहर बनाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम होगा।

आपका पक्ष

सोशल मीडिया का सदुपयोग जरूरी

संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। आज सोशल मीडिया के बढ़ते चलन से हर कोई अपनी बात रखने लगा है। लोकिन सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग बढ़ने के साथ-साथ इसका नकारात्मक उपयोग बढ़ने से यह सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। इससे निपटना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कई रूपों में किया जा रहा है। इसके जरिये सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा राजनीतिक हित के लिए गलत जानकारियां और भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे समाज में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच के बजाय समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी जोखिम रिपोर्ट में बताया है कि

सोशल मीडिया के ज़रिये झूठी सूचना का प्रसार उभरते जोखिमों में से एक है। लेकिन सवाल है कि एक प्रगतिशील समाज और देश के लिए यह कितना उचित है कि वह आए दिन गलत सूचनाओं को बनाए और साझा करे? सोशल मीडिया की वजह से फैल रही नफरत से देश संघर्ष कर रहा है। लेकिन यह भी सच है कि भारत में सोशल मीडिया के जरिये कई सकारात्मक कार्यों को भी अंजाम दिया गया है। वर्ष 2011 में अन्ना आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और निर्भया कांड के बाद एक सफल आंदोलन इसका सकारात्मक उदाहरण है। लेकिन वर्तमान में इसके गलत इस्तेमाल से सोशल मीडिया की विश्वनीयता कम होने लगी है। सोशल मीडिया का आज इतना दुरुपयोग होने लगा है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। गलत विचारों को साझा करने से देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में इसके खिलाफ कड़े कानून की सख्त जरूरत है। इसके लिए सरकार को मौलिक अधिकार के हनन से बचाव करते हुए कोई ठोस कानून बनाने की पहल करनी होगी। आम लोगों के लिए भी जरूरी है कि वे देशहित को प्राथमिकता दें और सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कर दुनिया के समक्ष भारत की बेहतर तस्वीर पेश करें। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इसे नफरत करने वाला देश बनने न दें।

सोशल मीडिया में अफवाहों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए कानून बनने चाहिए

अनु मिश्र, सीवान

सहकारी बैंकों में नए प्रबंधन की दरकार

सहकारी बैंकों की सहकारिता पर एक अध्ययन में यह पाया गया कि बैंकों के सहकारी चरित्र में गिरावट आ रही है। इन बैंकों की एजीएम में कम उपस्थिति, नए सदस्यों को स्वीकार करने में कई तरह की रोक टोक वाले दस्तूर, नए प्रबंधन के चुनावों में कम वोटिंग होना, एक ही प्रबंधन या परिवार के फिर से चुन लिए जाने, सर्वसम्मति से चुनाव न होना और एजीएम में सार्थक चर्चा के अभाव से इसके साफ संकेत मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि शहरी सहकारी बैंकों के संचालन में भारत क्यों एक प्रभावी तंत्र बनाने में विफल रहा है, जबकि समस्या अच्छी तरह से समझ लिए गए हैं। इसकी वजह सहकारी संगठनों की राजनीतिक संस्थाएं हैं और उनकी समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। लिहाजा सहकारी बैंकों में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति अहम है।

आरुषि गुप्ता, फरीदाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

दलीप कुमार

9 नवंबर

उच्चतम न्यायालय ने 70 साल पुराने मामले में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए सरकारी न्यास को सौंपने का फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी अन्य जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जगह दी जाए। शीर्ष अदालत ने दिसंबर में इस फैसले को लेकर दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं।

शासन

भारत के बारे में नए विचार

11 दिसंबर

संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों-हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए नागरिकता का रास्ता साफ किया गया है। पहली बार भारतीय नागरिकता के मापदंड के रूप में धर्म का इस्तेमाल किया गया, जिसके खिलाफ देश भर में विरोध-प्रदर्शन भड़क गए।

24 दिसंबर

प्रधानमंत्री ने कहा है कि विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि 16वीं जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) 2020 से 2021 के बीच होगी। सरकार ने एनपीआर और जनगणना दोनों के लिए 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

12 फरवरी

मंत्रिमंडल ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में अहम संशोधनों को मंजूरी दी। इससे खरीदारों के लिए ऋणग्रस्त परिसंपत्तियों को खरीदना आसान हो गया है। इसके अलावा रियल एस्टेट डेवलपरों के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने की न्यूनतम सीमा बढ़ाई गई है।

26 नवंबर

एन के सिंह (तस्वीर में) की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग को एक साल का विस्तार (अक्टूबर 2020 तक) दिया गया है। ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब वित्त आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इससे पहले 11वें वित्त आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया था, लेकिन यह विस्तार महज एक महीने के लिए था।

7 अक्टूबर

सरकार ने कांग्रेस की आपत्तियों को दरकिनार करके फ्रांस में बना राफेल लड़ाकू विमान हासिल किया। सरकार ने 36 विमानों का ऑर्डर दिया है। इस विमान को लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे।

19 अप्रैल

सर्वोच्च न्यायालय की एक पूर्व कर्मचारी ने अदालत के सभी न्यायाधीशों को पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई पर यौन शोषण का आरोप लगाया। मई में अदालत ने एक समिति गठित की, जिसने ऐसे मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं में से किसी को नहीं अपनाया। समिति ने गोगोई को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

11 दिसंबर

लोक सभा ने देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में सभी वित्तीय गतिविधियों के नियमन की खातिर एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर दिया, जिससे वित्तीय क्षेत्र में नियामकों के एक-दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं।

11 दिसंबर

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसने इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। आलोचकों ने विधेयक के विदेशी निवेश, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और इससे केंद्र को मिलने वाली शक्तियों पर असर को लेकर चिंता जताई है।

20 नवंबर

मंत्रिमंडल ने भारत पेट्रोलियम और शिपिंग कॉर्प में केंद्र की पूरी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी। इस तरह करीब दो दशक बाद निजीकरण के एजेंडे को फिर लाया गया है ताकि 2019-2020 में विनिवेश के अब तक के सबसे अधिक लक्ष्य को हासिल किया जा सके।